International Journal of Academic Excellence and Research (IJAER)
e-ISSN: 3107-3913 || Peer Reviewed || Open Access
Publication Impact Factor (I2OR) : 2.015
Vol. 02, No. 02, April-June, 2026, pp 70-77
© Copyright by MGM Publishing House (MGMPH)
www.mgmpublications.com

अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीति

डॉ. अजय सिंह कसाना*
सहायक आचार्य (भूगोल), राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिकंदरा
***Corresponding author:** kasanaas@gmail.com
Citation: कसाना, अजय (2026). अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीति. International Journal of Academic Excellence and Research, 02(02), 70–77. https://doi.org/10.62823/IJAER/02.02.206

सार: *इक्कीसवीं सदी की वैश्विक राजनीति में आर्थिक नीतियों और भू–राजनीतिक रणनीतियों के बीच की पारंपरिक सीमाएँ तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। वैश्वीकरण के प्रारंभिक चरण में जहाँ व्यापार को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक निर्भरता का माध्यम माना जाता था, वहीं वर्तमान दौर में व्यापार नीतियाँ शक्ति–संतुलन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भू–राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के प्रमुख उपकरण बन चुकी हैं। विशेष रूप से टैरिफ नीति अब केवल आर्थिक संरक्षण का साधन न होकर राज्यों की विदेश नीति और रणनीतिक सोच का अभिन्न अंग बन गई है। इसी व्यापक संदर्भ में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यह क्षेत्र न केवल वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति–श्रृंखला और समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र है, बल्कि अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य मंच भी बन चुका है। विश्व व्यापार के एक बड़े हिस्से का प्रवाह इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे यहाँ की आर्थिक नीतियाँ वैश्विक स्तर पर गहरे प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इस पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 में अपनाई गई टैरिफ नीति को केवल घरेलू आर्थिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता। 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति उस समय लागू की गई जब वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखलाएँ पुनर्गठन के दौर से गुजर रही थीं और रणनीतिक उद्योगों पर नियंत्रण को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जाने लगा था। अमेरिका ने इस नीति के माध्यम से इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के साथ–साथ क्षेत्रीय देशों के रणनीतिक आचरण को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि यह नीति व्यापार और भू–राजनीति के अंतर्संबंध को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन–विषय बन जाती है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध–पत्र 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति को इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीति के संदर्भ में विश्लेषित करता है और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार आर्थिक उपकरणों का उपयोग कर वैश्विक शक्ति–संतुलन को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है।*

Article History:
Received: 05 April, 2026
Revised: 20 April, 2026
Accepted: 27 April, 2026
Published Online: 06 May, 2026

शब्दकोश:
वैश्विक राजनीति, व्यापार नीतियाँ, टैरिफ नीति–2025, भू–राजनीति।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक व्यवस्था तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहाँ आर्थिक नीतियाँ, विशेषकर व्यापार और टैरिफ नीतियाँ, अब केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं रह गई हैं। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति–संतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी हैं। इसी संदर्भ में वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार व्यवस्था और विशेष रूप से इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीति को गहराई से प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। यह नीति ऐसे समय में लागू की गई है जब अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हो चुकी है और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक शक्ति

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by MGM Publishing House. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

संघर्ष का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 को केवल व्यापार संरक्षण या घरेलू उद्योगों के समर्थन के रूप में देखना अपर्याप्त होगा। यह नीति वास्तव में 'भू–आर्थिक रणनीति' का एक सशक्त उदाहरण है, जिसके माध्यम से अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रणनीतिक दबाव, आपूर्ति–श्रृंखला पुनर्गठन और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के साधन के रूप में प्रयोग किया है। विभेदित टैरिफ दरों के माध्यम से अमेरिका ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे चीन, भारत, जापान, दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्रों और ताइवान के साथ अपने संबंधों को अलग–अलग रणनीतिक स्तरों पर स्थापित करने का प्रयास किया है। यह नीति दर्शाती है कि वैश्विक व्यापार अब 'मुक्त व्यापार' के आदर्श से हटकर 'रणनीतिक व्यापार' की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का महत्व इस नीति के संदर्भ में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल वैश्विक उत्पादन, व्यापार और आपूर्ति–श्रृंखला का केंद्र है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति, तकनीकी उत्पादन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कारण यह क्षेत्र अमेरिका, चीन और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य मंच बन चुका है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ नीति का प्रभाव केवल आर्थिक लेन–देन तक सीमित न रहकर क्षेत्रीय गठबंधनों, सुरक्षा साझेदारियों और शक्ति–संतुलन को भी प्रभावित करता है। भारत के संदर्भ में यह नीति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च टैरिफ दरें उसकी आर्थिक और व्यापारिक हितों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार आसियान देशों और ताइवान के लिए यह नीति अवसर और दबाव दोनों का मिश्रित स्वरूप लेकर आती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और निर्भरता के नए समीकरणों को जन्म दे रही है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति का गहन विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि किस प्रकार यह नीति इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीतिक संरचना, शक्ति–संतुलन और क्षेत्रीय संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रही है। यह अध्ययन इस तर्क को स्थापित करने का प्रयास करता है कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था में व्यापार नीतियाँ अब आर्थिक निर्णयों से अधिक भू–राजनीतिक प्राथमिकताओं द्वारा संचालित हो रही हैं, और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र इस परिवर्तन की केन्द्रीय धुरी बन चुका है। प्रस्तुत शोध–पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

- अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 के स्वरूप और उसके भू–आर्थिक चरित्र का विश्लेषण करना।
- इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की व्यापार संरचना और अमेरिका के साथ उसके आर्थिक संबंधों का अध्ययन करना।
- अमेरिकी टैरिफ नीति के परिणामस्वरूप इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में उत्पन्न भू–राजनीतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
- भारत के संदर्भ में अमेरिकी टैरिफ नीति के विशेष भू–राजनीतिक प्रभावों का परीक्षण करना।

आंकड़ो के स्रोत एवं विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध–पत्र मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनका संकलन विश्वसनीय एवं आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से किया गया है। आँकड़ों के प्रमुख स्रोतों में Office of the United States Trade Representative (USTR), World Trade Organization (WTO), World Bank (WITS), U-S- Census Bureau] Asian Development Bank (ADB) तथा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें सम्मिलित हैं। अध्ययन में 2025 की अमेरिकी टैरिफ दरों, अमेरिका–इंडो–पैसिफिक व्यापार प्रवाह तथा देश–वार व्यापार संरचना से संबंधित आँकड़ों का चयन कर उनका तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। विधितंत्र के अंतर्गत वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए आँकड़ों को सारणीबद्ध किया गया

तथा भू–राजनीतिक व्याख्या के लिए भू–आर्थिक एवं भू–राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार आर्थिक आँकड़े और व्यापारिक प्रवृत्तियाँ इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती हैं।

2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति का स्वरूप

वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा लागू की गई टैरिफ नीति अपने स्वरूप, उद्देश्य और कार्यप्रणाली तीनों दृष्टियों से पूर्ववर्ती व्यापार नीतियों से भिन्न दिखाई देती है। यह नीति पारंपरिक अर्थों में केवल आयात शुल्क बढ़ाने या घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित रणनीतिक एवं भू–आर्थिक नीति के रूप में उभरती है। इस नीति का मूल उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रवाह को नियंत्रित करना, आपूर्ति–श्रृंखलाओं का पुनर्गठन करना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस नवीन अमेरिकी टैरिफ नीति का प्रमुख स्वरूप "Reciprocal and Differentiated Tariff Framework" पर आधारित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों पर समान दरों के बजाय अलग–अलग टैरिफ दरें लागू की गई हैं। यह विभेदीकरण केवल आर्थिक मानकों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक निकटता, रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग तथा भू–राजनीतिक महत्व जैसे कारकों पर आधारित है। इस प्रकार, टैरिफ नीति को अमेरिका ने एक ऐसे उपकरण के रूप में प्रयोग किया है जो व्यापारिक व्यवहार के साथ–साथ देशों के रणनीतिक आचरण को भी प्रभावित कर सके।

इस नीति के अंतर्गत कुछ देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया को अपेक्षाकृत कम टैरिफ दरों का लाभ मिला, जबकि भारत, वियतनाम और अन्य विकासशील इंडो–पैसिफिक देशों पर मध्यम से उच्च टैरिफ लगाए गए। वहीं चीन के मामले में उच्च और बहु–स्तरीय टैरिफ संरचना यह स्पष्ट संकेत देती है कि अमेरिकी टैरिफ नीति का एक केंद्रीय उद्देश्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों पर आर्थिक दबाव बनाना है। इस प्रकार, टैरिफ नीति "मित्र", "रणनीतिक साझेदार" और "रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के बीच स्पष्ट भेद स्थापित करती है। अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 का एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप इसका क्षेत्र–विशिष्ट और वस्तु–विशिष्ट चरित्र है। सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन और उन्नत तकनीकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ दरें यह दर्शाती हैं कि अमेरिका वैश्विक उत्पादन और तकनीकी नेतृत्व को सुरक्षित करने के लिए टैरिफ का उपयोग कर रहा है। यह नीति आपूर्ति–श्रृंखला निर्भरता को कम करने और 'China-centric manufacturing' से दूरी बनाने की रणनीति से भी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर, 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति का स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि यह नीति मुक्त व्यापार की पारंपरिक अवधारणा से हटकर रणनीतिक व्यापार नियंत्रण की दिशा में अग्रसर है। इसमें टैरिफ को आर्थिक नीति के बजाय भू–राजनीतिक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका प्रभाव न केवल व्यापार प्रवाह पर, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही स्वरूप आगे चलकर इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की भू–राजनीति को प्रभावित करने वाला एक निर्णायक कारक बनता है।

तालिका 1: अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 में लागू टैरिफ दरें

क्रम	देश / क्षेत्र	2025 में अमेरिकी टैरिफ दर (%)
1	भारत	25– 50 प्रतिशत
2	जापान	15 प्रतिशत
3	दक्षिण कोरिया	15 प्रतिशत
4	वियतनाम	20 प्रतिशत
5	ताइवान	20 प्रतिशत
6	इंडोनेशिया	19 प्रतिशत
7	थाईलैंड	19 प्रतिशत

8	मलेशिया	19–24 प्रतिशत
9	बांग्लादेश	20 प्रतिशत
10	पाकिस्तान	19 प्रतिशत
11	चीन	30 प्रतिशत से अधिक (बहु-स्तरीय)

Source: National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – USTR, Washington D.C.,2025

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति एक विभेदीकृत और रणनीति–आधारित ढाँचे पर आधारित है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के देशों पर समान टैरिफ दरें लागू न करके अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप अलग–अलग स्तर का आर्थिक दबाव बनाया है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे निकट रणनीतिक एवं सुरक्षा साझेदारों पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ दरें लागू की गई हैं, जबकि भारत, वियतनाम और आसियान देशों पर मध्यम से उच्च टैरिफ दरें लगाई गई हैं। चीन पर सबसे अधिक और बहु–स्तरीय टैरिफ लागू होना यह दर्शाता है कि अमेरिकी नीति का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों पर आर्थिक नियंत्रण और दबाव बनाना है। औसत प्रभावी टैरिफ दर का 17–21 प्रतिशत के बीच होना यह संकेत देता है कि अमेरिका ने मुक्त व्यापार की परंपरागत नीति से हटकर संरक्षणवादी और भू–आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया है। उच्चतम टैरिफ दरों का 40–50 प्रतिशत तक पहुँचना यह दर्शाता है कि टैरिफ को केवल राजस्व या व्यापार संतुलन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक अनुशासन और भू–राजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत करता है कि अमेरिकी टैरिफ नीति वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखला और रणनीतिक उद्योगों के पुनर्गठन से सीधे जुड़ी हुई है।

इंडो–पैसिफिक व्यापार संरचना

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र बन चुका है। यह क्षेत्र न केवल वैश्विक उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति–श्रृंखलाओं, समुद्री व्यापार मार्गों और तकनीकी विनिर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। अमेरिका, चीन, जापान, भारत, दक्षिण–पूर्व एशियाई देश और ताइवान सभी इस क्षेत्र की व्यापार संरचना को आकार देते हैं। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 का प्रभाव तभी ठीक से समझा जा सकता है जब इंडो–पैसिफिक की मौजूदा व्यापार संरचना को स्पष्ट रूप से देखा जाए। इंडो–पैसिफिक व्यापार संरचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार असमान है। अधिकांश देशों के मामले में अमेरिका का आयात, निर्यात की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे अमेरिका को टैरिफ के माध्यम से दबाव बनाने की अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ नीति इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सिद्ध होती है।

तालिका 2: अमेरिका–इंडो–पैसिफिक प्रमुख देशों का व्यापार, 2025

(अरब डॉलर में)

देश	अमेरिका का निर्यात	अमेरिका का आयात	कुल व्यापार
चीन	82.0	242.4	324.4
ताइवान	39.8	134.2	174.0
जापान	61.5	110.0	171.5
वियतनाम	10.8	140.3	151.1
दक्षिण कोरिया	51.1	95.6	146.7
भारत	33.7	80.8	114.5

Source: U.S. Census Bureau, 2025, BEA, 2025

अमेरिका–इंडो–पैसिफिक प्रमुख देशों का व्यापार, 2025

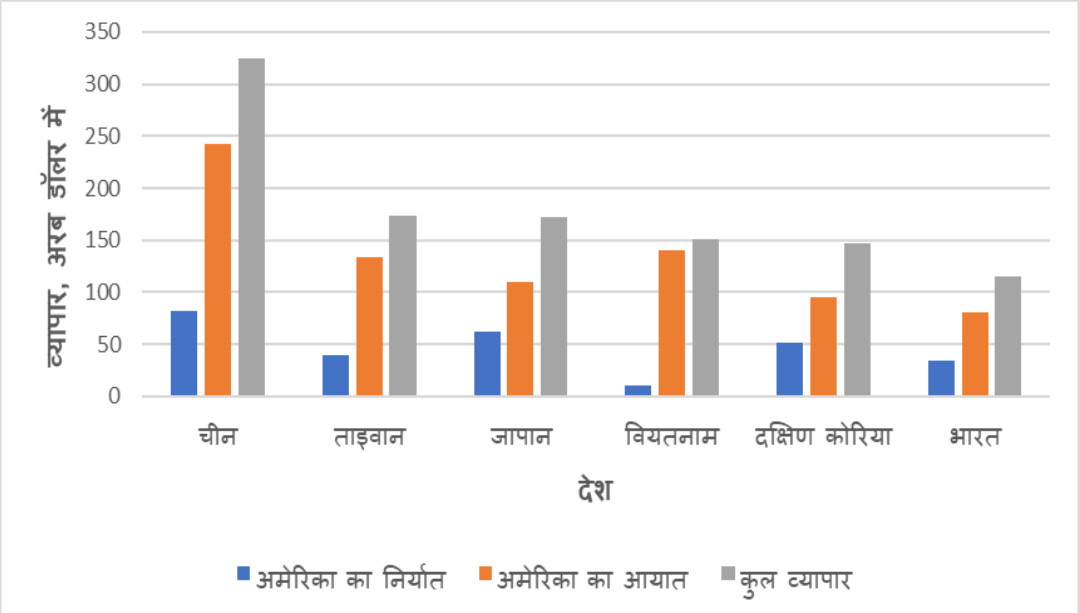

उक्त तालिका स्पष्ट करती है कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बना हुआ है। विशेष रूप से चीन, वियतनाम और ताइवान के मामले में आयात निर्यात की तुलना में कहीं अधिक है। यही व्यापारिक असंतुलन नवीन अमेरिकी टैरिफ नीति, 2025 का एक प्रमुख आधार बनता है, क्योंकि उच्च आयात–निर्भरता वाले देशों पर टैरिफ का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। इंडो–पैसिफिक व्यापार संरचना यह स्पष्ट करती है कि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र होने के साथ–साथ अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र भी है। उच्च व्यापार निर्भरता, निर्यात–प्रधान अर्थव्यवस्थाएँ और असंतुलित द्विपक्षीय व्यापार संबंध अमेरिका को टैरिफ के माध्यम से रणनीतिक दबाव बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार, इंडो–पैसिफिक की व्यापार संरचना नवीन अमेरिकी टैरिफ नीति को केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि प्रभावी भू–राजनीतिक उपकरण में परिवर्तित कर देती है।

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी टैरिफ नीति का भू–राजनीतिक प्रभाव

आंकड़े स्पष्ट करतें है कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 का प्रभाव केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने क्षेत्रीय भू–राजनीति, शक्ति–संतुलन और रणनीतिक गठबंधनों की दिशा को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में अमेरिका, चीन, भारत, जापान, दक्षिण–पूर्व एशियाई देश और ताइवान जैसे प्रमुख शक्ति–केंद्र मौजूद हैं, जिनके आर्थिक और सुरक्षा हित आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ नीति एक ऐसे साधन के रूप में उभरती है, जिसके माध्यम से अमेरिका ने आर्थिक दबाव के जरिए भू–राजनीतिक उद्देश्यों को साधने का प्रयास किया है। 2025 की टैरिफ नीति के अंतर्गत अमेरिका ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के देशों पर समान व्यवहार नहीं किया। रणनीतिक साझेदारों और सुरक्षा सहयोगियों पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाए गए, जबकि कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर उच्च या बहु–स्तरीय टैरिफ लागू किए गए। उदाहरण के लिए जापान और दक्षिण कोरिया पर लगभग 15 प्रतिशत की टैरिफ दरें लागू होना यह संकेत देता है कि अमेरिका ने अपने सुरक्षा सहयोगियों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान की, जबकि चीन पर 30 प्रतिशत से अधिक की प्रभावी टैरिफ दरें यह दर्शाती हैं कि टैरिफ नीति को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के हथियार के रूप में उपयोग किया गया।

तालिका 3: अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रमुख भू–राजनीतिक प्रभाव

क्षेत्र/देश समूह	टैरिफ नीति का स्वरूप	प्रमुख भू-राजनीतिक प्रभाव
चीन	उच्च व बहु-स्तरीय टैरिफ	रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, डिकपलिंग
जापान	कम टैरिफ	सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना
दक्षिण कोरिया	कम टैरिफ	सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना
भारत	मध्यम-उच्च टैरिफ	सहयोग एवं रणनीतिक दबाव
आसियान देश	मध्यम टैरिफ	रणनीति को बढ़ावा
ताइवान	मध्यम टैरिफ	तकनीकी व सुरक्षा महत्व

Source: compilation based on USTR (2025) tariff data and U.S. Census Bureau (2025) trade statistics; interpreted using Brookings Institution and CFR policy analyses.

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की व्यापार संरचना को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका के साथ अधिकांश देशों का व्यापार असंतुलित है, जहाँ अमेरिका का आयात निर्यात की तुलना में अधिक है। उदाहरणस्वरूप, 2025 में अमेरिका–चीन कुल व्यापार लगभग 324 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के साथ भी अमेरिकी आयात अत्यधिक रहा। यह असंतुलन अमेरिका को टैरिफ के माध्यम से दबाव बनाने की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण अमेरिकी टैरिफ नीति इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता को भू–राजनीतिक प्रभाव में परिवर्तित करने का माध्यम बन जाती है। अमेरिकी टैरिफ नीति का एक महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक प्रभाव चीन–विरोधी रणनीति के रूप में सामने आता है। उच्च टैरिफ और तकनीकी उत्पादों पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका ने न केवल चीन की निर्यात–क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखलाओं को चीन–केंद्रित ढाँचे से हटाकर भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों की ओर स्थानांतरित करने को भी प्रोत्साहित किया है। इससे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में नए उत्पादन–केंद्र उभरने लगे हैं, जो क्षेत्रीय भू–राजनीति को पुनःआकार दे रहे हैं।

भारत के संदर्भ में अमेरिकी टैरिफ नीति का भू–राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक ओर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार और क्वाड समूह (फनंक) जैसे मंचों का सक्रिय सदस्य है, वहीं दूसरी ओर उच्च टैरिफ दरें भारत की आर्थिक स्वायत्तता और व्यापारिक हितों के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि अमेरिकी टैरिफ नीति सहयोग और दबाव दोनों का मिश्रित रूप अपनाए हुए है, जो भारत सहित अन्य इंडो–पैसिफिक देशों को अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कुल मिलाकर, 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, सुरक्षा और रणनीति के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। यह नीति यह संकेत देती है कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आर्थिक नीतियाँ अब स्वतंत्र नहीं रहीं, बल्कि वे सीधे–सीधे भू–राजनीतिक उद्देश्यों से जुड़ चुकी हैं। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट और सक्रिय उदाहरण बनकर उभरा है।

भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 का विशेष भू–राजनीतिक प्रभाव

अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 का भारत पर प्रभाव केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से भू–राजनीतिक भी है। एक ओर भारत के रूप में उभरती हुई अर्थव्यवस्था और इंडो–पैसिफिक रणनीति का प्रमुख स्तंभ है, वहीं दूसरी ओर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। ऐसे संदर्भ में अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 भारत–अमेरिका संबंधों में सहयोग और दबाव के द्वंद्व को उजागर करती है। अमेरिका द्वारा भारत पर मध्यम से उच्च 25 से 50 प्रतिशत तक की टैरिफ दरों का लागू होना यह संकेत देता है कि भारत को पूर्ण व्यापारिक रियायत प्राप्त नहीं है, भले ही वह रणनीतिक साझेदार माना जाता हो। यह स्थिति दर्शाती है कि अमेरिकी नीति–निर्माण में भारत को एक ऐसे भागीदार के रूप में देखा जा रहा है, जो चीन का विकल्प तो है, परंतु जिसे आर्थिक दबाव के माध्यम से

नीति–अनुकूलता की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। अतः यह टैरिफ नीति भारत के लिए केवल निर्यात–लागत की समस्या नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा प्रश्न बन जाती है।

भू–राजनीतिक दृष्टि से भारत की भूमिका इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत विशेषकर क्वाड समूह (फनंक) जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और नियम–आधारित व्यवस्था के समर्थन में अमेरिका के साथ सहयोग करता है। इसके बावजूद उच्च टैरिफ दरें यह दर्शाती हैं कि अमेरिका आर्थिक उपकरणों का उपयोग कर भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखना चाहता है। यह दबाव भारत को वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखला पुनर्गठन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने अमेरिकी बाजार पर निर्भरता बढ़ाने तथा कुछ रणनीतिक नीतिगत विकल्पों में अमेरिका–अनुकूल रुख अपनाने की दिशा में प्रभावित कर सकता है।

तालिका 4: भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रमुख भू–राजनीतिक संकेत

आयाम	2025 में स्थिति	भू-राजनीतिक संकेत
टैरिफ दर	25–50 प्रतिशत	आर्थिक दबाव के माध्यम से रणनीतिक प्रभाव
व्यापार आकार	114 अरब डॉलर	अमेरिकी बाजार पर निर्भरता
रणनीतिक साझेदारी	क्वाड समूह (Quad) एवं इंडो-पेसिफिक	सुरक्षा सहयोग मजबूत
नीति-स्वरूप	सहयोग एवं दबाव दोनों	संतुलित परंतु असमान संबंध
संभावित प्रभाव	आपूर्ति-श्रृंखला में बदलाव	भारत की क्षेत्रीय भूमिका में वृद्धि

Source: Office of the United States Trade Representative (USTR), 2025), India Country Trade Barriers Report, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 2025.

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है की भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति एक द्वैध रणनीति पर आधारित है जहाँ सुरक्षा और भू–राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है वहीं आर्थिक टैरिफ के माध्यम से नीति–अनुकूलता का दबाव भी बनाए रखा जाता है। इससे भारत–अमेरिका संबंधों की जटिलता और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका दोनों स्पष्ट होती हैं। आर्थिक आँकड़ों के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2025 में भारत–अमेरिका कुल व्यापार लगभग 114 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रहा, जिसमें अमेरिका का आयात भारत से निर्यात की तुलना में अधिक रहा। यह असंतुलन अमेरिका को टैरिफ के माध्यम से प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। उच्च टैरिफ के कारण भारत के वस्त्र, रत्न–आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और कुछ विनिर्माण क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है, जिसका असर निवेश निर्णयों और आपूर्ति–श्रृंखला रणनीतियों पर भी पड़ता है। समग्र रूप से आंकलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति का भू–राजनीतिक प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि अमेरिका भारत को केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक गणना के हिस्से के रूप में देखता है। यह नीति भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करती है। अवसर इसलिए कि वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखला में उसकी भूमिका बढ़ सकती है, और चुनौती इसलिए कि उच्च टैरिफ उसकी आर्थिक स्वायत्तता और नीति–निर्णयों पर दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार, 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति भारत–अमेरिका संबंधों को एक नए, अधिक जटिल भू–राजनीतिक चरण में ले जाती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अमेरिकी टैरिफ नीति–2025 पारंपरिक व्यापार संरक्षण की नीति न होकर एक भू–आर्थिक एवं भू–राजनीतिक रणनीति के रूप में कार्य कर रही है। अमेरिका ने टैरिफ को केवल राजस्व या व्यापार संतुलन सुधारने के साधन के बजाय रणनीतिक दबाव, आपूर्ति–श्रृंखला पुनर्गठन और शक्ति–संतुलन प्रभावित करने के उपकरण के रूप में अपनाया है। इस नीति का प्रभाव इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक परिलक्षित होता है, क्योंकि यही क्षेत्र वैश्विक व्यापार, तकनीकी उत्पादन और सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि अमेरिका ने इंडो–पैसिफिक देशों के प्रति विभेदीकृत टैरिफ

दृष्टिकोण अपनाया है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे निकट सुरक्षा साझेदारों को अपेक्षाकृत कम टैरिफ राहत मिली, जबकि भारत आसियान देशों और विशेष रूप से चीन पर मध्यम से उच्च अथवा बहु–स्तरीय टैरिफ लागू किए गए। भारत के संदर्भ में अध्ययन यह दर्शाता है कि अमेरिका की टैरिफ नीति सहयोग और दबाव की द्वैध रणनीति का उदाहरण है। एक ओर भारत को इंडो–पैसिफिक रणनीति का प्रमुख स्तंभ और चीन के विकल्प के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च टैरिफ दरें भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार, भारत–अमेरिका संबंध 2025 के बाद एक अधिक जटिल और बहुआयामी भू–राजनीतिक चरण में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि नवीन अमेरिकी टैरिफ नीति– 2025 ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को एक नए भू–राजनीतिक युग में प्रवेश करा दिया है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र इस परिवर्तन का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है, जहाँ व्यापार, राजनीति और रणनीति एक–दूसरे में विलीन होते दिखाई देते हैं। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए इस बदलती वैश्विक व्यवस्था को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

References

1. Asian Development Bank. (2023). *Asian economic integration report 2023: Trade, investment, and supply chains*. Asian Development Bank.
2. Brookings Institution. (2024). *Geo-economics and U.S. trade policy in the Indo-Pacific*. Brookings Institution.
3. Congressional Research Service. (2024). *U.S. trade policy and tariff measures*. U.S. Congress.
4. Council on Foreign Relations. (2024). *The United States, China, and Indo-Pacific economic competition*. CFR.
5. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. (2024). *India–U.S. trade and economic relations*. Government of India.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Trade policy implications in the Asia-Pacific region*. OECD Publishing.
7. Peterson Institute for International Economics. (2024). *U.S. tariffs, protectionism, and global trade flows*. PIIE.
8. United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023: International supply chains*. UNCTAD.
9. United States Census Bureau. (2025). *Foreign trade statistics: Top trading partners*. U.S. Department of Commerce.
10. United States Trade Representative. (2025). *National trade estimate report on foreign trade barriers*. Office of the United States Trade Representative.
11. World Bank. (2023). *World integrated trade solution (WITS) database*. World Bank.
12. World Trade Organization. (2024). *World tariff profiles 2024*. WTO.

❑❑❑